रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925

No. 152] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सा०का०नि० 264(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं0आ0 198"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2003 है ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2002 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारित होंगी, जो राज्यों को राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में,-

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राशियां उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (14) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जो उन स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने और "विशेष समस्याओं" के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् :-

935 GI 2003

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए

राज्य	जिला प्रशासन	पुलिस प्रशासन	कारागार प्रशासन	अग्नि	न्यायिक	राजकोषीय	स्वास्थ्य	प्रारंभिक शिक्षा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सार्वजनिक पुस्तकालय	विरासत संरक्षण	पारंपरिक जल स्रोतों की वृद्धि	विशेष समस्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						(रु० लाख में)							
आंध्र प्रदेश	..	441.46	..	682.69	1244.50	..	723.96	1025.61	790.66	..	..	..	855.87
अरुणाचल प्रदेश	..	..	301.65	..	..	50.00	..	.	449.89	36.00	60.32	301.95	30.25
असम	..	..	..	..	293.20	150.00	..	..	..	..	..	..	..
बिहार	..	..	385.50	..	2636.35	..	..	..	479.92	..	203.01	..	787.56
छत्तीसगढ़	1594.82	66.87	..	147.60	437.57	157.50	120.66	..	550.02	..	..	186.30	..
गोवा	..	..	..	..	69.20	..	..	..	..	..	..	..	..
गुजरात	..	..	..	392.14	..	..	542.97	..	..	479.67	..	931.48	..
हरियाणा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	95.94	..
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..	50.00	271.50	..	155.66	..	79.56	..	..
जम्मू-कश्मीर	..	..	..	..	168.27	50.00	..	..	..	..	..	..	..
झारखंड	..	..	..	..	1282.83	98.00	452.47	..	..	..	..	..	25.03
कर्नाटक	2111.55	..	..	..	1345.06	..	..	..	..	447.30	..	..	..
केरल	..	278.72	13.58	..	28.76..	..	..	20.11	..	..	..	129.71	..
मध्य प्रदेश	..	..	..	..	1230.06	..	..	..	..	..	..	..	..
महाराष्ट्र	..	1085.82	241.32	603.30	..	..	814.47	..	..	..	..	1533.58	1809.88
मणिपुर	150.82	115.83	30.16	30.16	..	50.00	..	30.06	..	223.85	30.16	118.24	211.05
मेघालय	..	..	..	..	49.78	50.00	..	..	..	..	..	..	..
मिजोरम	..	66.36	50.28	20.11	49.78	50.00	..	30.16	..	181.72	..	114.63	..
नागालैंड	..	..	..	..	18.30	50.00	..	..	171.24	181.72	..	..	1244.51
उड़ीसा	..	..	..	..	1032.44	..	..	..	..	559.61	..	..	452.50

पंजाब	..	..	..	..	412.68	..	..	..	..	..	..	..	..
राजस्थान	..	89.73	298.68	442.42	1198.20	..	..	..	..	368.37	..	1590.89	1536.93
सिक्किम	..	16.89	..	30.16	..	50.00	60.33	..	..	143.90	30.16	..	..
तमिलनाडु	..	110.73	..	160.88	583.99	..	422.31	..	1121.61	68.00	..	557.16	..
त्रिपुरा	301.65	174.96	30.16	30.16	40.82	50.00	..	..	51.89	..	..	..	905.09
उत्तर प्रदेश	..	..	254.39	..	3495.55	..	..	..	..	..	.	..	..
उत्तरांचल	922.75	88.67	66.06	99.9	649.13	141.00	271.48	..	..	..	..	..	301.65
पश्चिमी बंगाल	..	..	90.5	120.66	..	..	241.32	..	..	..	..	..	..

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सैक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि का, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत उस वास्तविक व्यय के विरुद्ध, जो कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर समायोजन किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिससे सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिए जाने हैं ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (8) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जो 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उन स्तम्भों में उल्लखित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर और "विशेष समस्याओं" पर पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् :-

सारणी

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए						
	पुलिस	कोषागारों का कंप्यूटरीकरण	जेल	अभिलेख कक्ष	शिक्षा	अग्निशमन सेवाएं	विशेष समस्याएं
1	2	3	4	5	6	7	8
				(रु0 लाख मे)			
आंध्र प्रदेश	60.55	-	-	-	-	40.00	-
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	15.68	-
बिहार	38.00	-	32.40	185.59	1455.92	24.17	-
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	9.80	-	29.91	369.90
झारखण्ड	124.55	-	37.74	-	-	6.77	-
मणिपुर	2.65	-	-	-	21.82	-	292.98
मेघालय	-	-	0.37	-	-	-	-
उड़ीसा	6.36	-	-	8.50	217.94	-	137.10
सिक्किम	2.42	0.01	1.35	0.01	-	51.75	25.00
उत्तर प्रदेश	-	-	-	498.65	-	-	-
उत्तरांचल	-	-	-	19.67	-	-	-

परन्तु यह कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि को किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

[फा० सं० 19(4)/2003-वि०-I]
सुभाष सी० जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 264(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

" C.O. 198 "

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 7 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues to—

(*a*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (14) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and "special problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

Table

For upgradation of Standards relating to

State	District Administration	Police Administration	Jail Administration	Fire	Judicial	Fiscal	Health	Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection	Augmentation of Traditional Water Sources	Special Problem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					(Rupees in lakhs)								
Andhra Pradesh	...	441.46	...	682.69	1244.50	...	723.96	1025.61	790.66	...	...	...	855.87
Arunachal Pradesh	...	...	301.65	...	...	50.00	...	...	446.89	36.00	60.32	301.95	30.25
Assam	...	...	...	...	293.20	150.00	...	...	...	...	...	...	...
Bihar	...	...	385.50	...	2636.35	...	...	...	479.92	...	203.01	...	787.56
Chhattisgarh	1594.82	86.87	...	147.60	437.57	157.50	120.66	...	550.02	...	...	186.30	...
Goa	...	...	...	...	69.20	...	...	...	...	...	...	...	...
Gujarat	...	...	...	392.14	...	...	542.97	...	...	479.67	...	931.48	...
Haryana	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	95.94	...
Himachal Pradesh	...	...	...	...	...	50.00	271.50	...	155.66	...	79.56	...	...
Jammu and Kashmir	...	...	...	...	166.27	50.00	...	...	...	...	...	...	...
Jharkhand	...	...	...	...	1282.83	98.00	452.47	...	...	...	...	...	25.03
Karnataka	2111.55	...	...	...	1345.06	...	...	...	...	447.30	...	...	...
Kerala	...	278.72	13.58	...	28.76	...	...	20.11	...	...	...	129.71	...
Madhya Pradesh	...	...	...	...	1230.06	...	...	...	...	...	...	...	...
Maharashtra	...	1085.82	241.32	603.30	...	...	814.47	...	...	...	...	1533.58	1809.88
Manipur	150.82	115.83	30.16	30.16	...	50.00	...	30.06	...	223.85	30.16	118.24	211.05
Meghalaya	...	...	...	...	49.78	50.00	...	...	...	...	...	...	...
Mizoram	...	66.36	50.28	20.11	49.78	50.00	...	30.16	...	181.72	...	114.63	...
Nagaland	...	...	...	...	18.30	50.00	...	...	171.24	181.72	...	...	1244.51
Orissa	...	...	...	...	1032.44	...	...	...	...	559.61	...	...	452.50
Punjab	...	...	...	...	412.68	...	...	...	...	...	...	...	...
Rajasthan	...	89.73	298.68	442.42	1198.20	...	...	...	...	368.37	...	1590.89	1536.93
Sikkim	...	16.89	...	30.16	...	50.00	60.33	...	...	143.90	30.16	...	...
Tamil Nadu	...	110.73	...	160.88	583.99	...	422.31	...	1121.61	68.00	...	557.16	...
Tripura	301.65	174.96	30.16	30.16	40.82	50.00	...	...	51.89	...	...	...	905.09
Uttar Pradesh	...	...	254.39	...	3495.55	...	...	...	...	...	...	...	...
Uttaranchal	922.75	88.67	66.06	99.9	649.13	141.00	271.48	...	...	...	...	...	301.65
West Bengal	...	...	90.5	120.66	...	...	241.32	...	...	...	...	...	...

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 2002 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as reflected in the accounts of that years:

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remain unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States;

(*b*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (8) of the said Table, towards expenditure of capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgradation of Standards and "special problems" mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, namely:—

Table

State	Police	For upgradation of standards relating to					
		Computarisation Treasuries	Jails	Record Rooms	Education	Fire Services	Special Problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Rupees in lakhs)					
Andhra Pradesh	60.55	—	—	—	..	40.00	—
Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	15.68	..
Bihar	38.00	—	32.40	185.59	1455.92	24.17	—
Jammu and Kashmir	—	—	—	9.80	—	29.91	369.90
Jharkhand	124.55	—	37.74	—	—	6.77	—
Manipur	2.65	—	—	—	21.82	—	292.98
Meghalaya	—	—	0.37	—	—	—	—
Orissa	6.36	—	—	8.50	217.94	—	137.10
Sikkim	2.42	0.01	1.35	0.01	—	51.75	25.00
Uttar Pradesh	—	—	—	498.65	—	—	—
Uttaranchal	—	—	—	19.67	—	..	—

Provided that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(4)/2003-L-I]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

935 GI/03 -2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.